

RTI Act, 2005

Regd. Post/By Special Messenger

Most Immediate/Time Bound.

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,

सह
कार्यकारी निर्देशक, पारितिविज फिलिम लिमिटेड, दूरस्थनिष्ठासिमेंट,
B-9, कुटुंब इंडस्ट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर, कलकत्ता 700016,
गड वि.सी. - 110006

विषय:- सूचना के अधिकार के तहत आर. टी0 आई0 ऐक्ट 2005 में पारित विधेयक जनहित में पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार न हो।

महाशय,

उपरोक्त ऐक्ट के संबंधव में सादर कहना है कि आ0टी0आई0 ऐक्ट प्रयोग सर्वप्रथम 1776 ई0 में स्वीडेन में हुआ था। आर0टी0आई0 ऐक्ट अन्तराष्ट्रीय स्तर पर 1923 ई0 में प्रचलन में है। 2005 में भारत के सर्वोच्च अधिकार के पहल पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आदेश से बना विधेयक के ऐक्ट के तहत उपधारा-8 एवं 9 में उल्लिखित 22 एजेंसियों की सूची हो गई है। फिर भी यदि सूचना हनन भ्रष्टाचार के आरोपों या मानवाधिकार के हनन से जुड़ी है, तो उक्त ऐक्ट के तहत सूचना देनी पड़ेगी। प्रपत्र "क" के अन्तर्गत आर0टी0आई0 ऐक्ट की धारा 6(2) में स्पष्ट कहा गया है कि आवेदक से सूचना मांगने का कारण नहीं पुछा जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम इस तथ्य पर आधारित है कि जनता टैक्स देती है इसलिए उन्हें जानने का अधिकार है कि उनका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। इसका सरकारी तंत्र किस तरह से कार्य कर रहा है। इसलिए जनता को सरकार के हर पक्ष से सब कुछ जानने का अधिकार है। यदि मुद्रा प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा या न जुड़ा हो।

1974 ई0 में भारत सरकार न्यायपालिका में पारदर्शिता शत प्रतिशत लाने के लिए सदर एस0डी0ओ से छीनकर (कौगनिजेन्स पावर) सी0जे0एम0 महोदय को सुपुर्द किया गया। क्योंकि उनसे सही ढंग से कानून का उपयोग नहीं हो रहा था। यदि आप हमारे आवेदन का उत्तर सही समय पर नहीं देंगे तो प्रथम अपीलीय प्राधिकार माननीय कोर्टोनी न्याय
भारत सरकार
→ करेंगे। ये महोदय भी सही समय पर जबाब नहीं देंगे तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त महोदय से करेंगे। इस प्रकार धारा-226 के तहत के तहत उच्च न्यायालय पटना या धारा-32 के तहत उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली जाना पड़ेगा।

विश्वासभाजन

सुधांशु शर्मा

नेशनल आर0टी0आई0 एवार्ड के वरिष्ठतम

कार्यकर्ता ग्राम+पो0-पड़री, भाया-बनगाँव, जिला-सहरसा।

मो नं0-9661088793

रितिका
23/12/2013

